भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2070 का उत्तर

कर्नाटक में चल रही/स्वीकृत रेलवे परियोजनाओं की स्थिति

2070. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में नई लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और उपनगरीय रेल परियोजनाओं सहित चल रही/स्वीकृत रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई है और पूरा होने की निर्धारित तथा संशोधित समय सीमा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और यदि इनमें देरी हुई तथा लागत में वृद्धि हुई है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी और वित्तीय योगदान के संदर्भ में कर्नाटक सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है और क्या राज्य सरकार की ओर से समय पर सहायता की कमी ने किसी परियोजना की प्रगति को प्रभावित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मुद्दों के समाधान और कर्नाटक में रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	835 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	7,564 करोड़ रु. (9 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 3,264 किलोमीटर लंबाई की 25 परियोजनाएं (15 नई लाइनें, 10 दोहरीकरण) जिनकी लागत 42,517 करोड़ रु. है, स्वीकृत की गई हैं। इनका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	15	2,034	421	8,794
दोहरीकरण/ बहुपथन	10	1,230	973	12,516
कुल	25	3,264	1,394	21,310

कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	कोत्तूर-हरिहर नई लाइन (65 किलोमीटर)	468
2	हासन-बेंगलुरु नई लाइन (167 किलोमीटर)	1,290
3	बीदर-गुलबर्गा नई लाइन (110 किलोमीटर)	1,543
4	शिवानी-होसदुर्ग सड़क दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	50
5	शिवानी-बिरुर दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	143
6	होसदुर्ग-चिकजाजुर दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	260
7	रामनगरम-मैसूरु कहीं-कहीं दोहरीकरण (94 किलोमीटर)	998
8	यलहंका-चन्नसंद्रा दोहरीकरण (13 किलोमीटर)	108
9	यशवंतपुर-यलहंका दोहरीकरण (12 किलोमीटर)	95
10	नेत्रावती-मंगलौर सेंट्रल दोहरीकरण (2 किलोमीटर)	28
11	कनकनाडि-पनम्बूर दोहरीकरण (19 किलोमीटर)	350
12	अरसीकेरे-तुमकूर दोहरीकरण (96 किलोमीटर)	758
13	यलहंका-पेनुकोंडा दोहरीकरण (123 किलोमीटर)	1,104
14	दौंड-गुलबर्गा दोहरीकरण (225 किलोमीटर)	3,182
15	हुबली-चिकजाजुर दोहरीकरण (190 किलोमीटर)	1,850

कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जो शुरू की गई हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	होसपेट-हुबली-लोंडा-वास्को-द-गामा दोहरीकरण (312 किलोमीटर)	4,153
2	होटगी-गदग दोहरीकरण (284 किलोमीटर)	2,459
3	गिणिगेरा - रायचूर नई लाइन (165 किलोमीटर)	3,401
4	गदग - वाडी नई लाइन (257 किलोमीटर)	2,842
5	बागलकोट - कुडची नई लाइन (142 किलोमीटर)	1,649
6	तुमकूर - रायदुर्ग नई लाइन (207 किलोमीटर)	2,496
7	तुमकूर - दावणगेरे नई लाइन (182 किलोमीटर)	2,142
8	कडूर - चिकमगलूर-बेलूर नई लाइन (68 किलोमीटर)	825
9	बैयप्पनहल्ली - होसुर दोहरीकरण (48 किलोमीटर)	336
10	यशवंतपुर - चन्नसंद्रा दोहरीकरण (22 किलोमीटर)	314

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 7,240 किलोमीटर लंबाई के 65 सर्वेक्षण कार्य (25 नई लाइन और 40 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण के कारण लंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	परियोजना	अपेक्षित कुल भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण किए जाने हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	शिमोगा - राणिबेन्नुर नई लाइन (96 किलोमीटर)	559	226	333
2	बेलगाम - धारवाड नई लाइन (73 किलोमीटर)	581	0	581
3	शिमोगा - हरिहर नई लाइन (79 किलोमीटर)	488	0	488
4	व्हाइटफील्ड-कोलार नई लाइन (53 किलोमीटर)	337	0	337
5	हासन-बेलूर नई लाइन (32 किलोमीटर)	206	0	206

कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण की स्थिति का सारांश इस प्रकार है:-

कर्नाटक में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	9,064 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	5,707 हेक्टेयर (63%)
अधिग्रहण हेतु शेष भूमि	3,357 हेक्टेयर (37%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, बहरहाल इनकी सफलता कर्नाटक राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात अनुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई आरंभिक और अंतिम स्थान तक संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालन संबंधी आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंजूरी
- अतिलंघी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरियाँ
- क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक स्थिति
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने वाले महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं

बेंगलुरु उपनगरीय:

रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (के-राइड), जो कर्नाटक राज्य सरकार (51% इक्विटी) द्वारा नियंत्रित एक कंपनी है, बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना (बीएसटीपी) को निष्पादित कर रही है। बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना (148.17 कि.मी.) को ₹15767 करोड़ की लागत पर स्वीकृति दी गई है, जिसमें भारत सरकार और कर्नाटक सरकार प्रत्येक द्वारा 20% वित्तपोषण किया जाएगा और 60% वित्तपोषण ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना में चार गलियारे हैं, नामतः,

गलियारा-1: केएसआर बेंगलुरु सिटी-देवनहल्ली (41.4 किलोमीटर)

गलियारा-2: बायपनहल्ली - चीक्कबाणावार (25.01 किलोमीटर)

गलियारा-3: केंगेरी-व्हाइटफील्ड (35.52 किलोमीटर)

गलियारा-4: हीललिगे-राजनकुंटे (46.25 किलोमीटर)

गलियारा-2 और 4 पर कार्य प्रगति पर है। गलियारा 1 और 3 के लिए के-राइड द्वारा प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। भारतीय रेल ने परियोजना के लिए रेल भूमि के-राइड को हस्तांतरित कर दी है, बहरहाल, राज्य सरकार की भूमि के हस्तांतरण की प्रगति बहुत धीमी है।

रेल मंत्रालय ने बी.एस.टी.पी. परियोजना के लिए अब तक 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब तक बी.एस.टी.पी. परियोजना पर 2,385 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

रेल विद्युतीकरण

भारतीय रेल में रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया गया है। अब तक, बड़ी लाइन नेटवर्क का लगभग 99.4% विद्युतीकृत किया जा चुका है। शेष नेटवर्क में विद्युतीकरण

कार्य शुरू हो गया है। वर्ष 2014-25 के दौरान और वर्ष 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	मार्ग किलोमीटर
2014 से पहले (लगभग 60 वर्ष)	21,801
2014-25	46,900

कर्नाटक में, 97% बड़ी लाइन नेटवर्क को विद्युतीकृत किया गया है और शेष नेटवर्क में विद्युतीकरण का कार्य शुरु किया गया है।

******